



प्रमाणित अति राज्यकार्य श्री गंगाधर सिंह 25/11/20



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्या: 50/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00076

1. गंगाराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी मोटासर खूनी हाल सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती केसर पत्नि श्री बृज लाल जाति सुथार निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. चेताराम वल्द दलूराम जाति सुथार निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बृजमोहन पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजस जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्ट्स

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये भू-धारक प्रतिनिधि तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. ज्ञान सिंह पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सत्यनारायण पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी 10 एस पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. भागीरथ पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्नेहलता पुत्री श्री बृजमोहन जाति सुथार निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. रूखसाना पत्नि श्री रजाकअली जाति मुसलमान कायमखानी निवासी हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंट्स

मितान किया

9

उपस्थित: श्री महावीर प्रसाद शर्मा
श्री विजय कुमार पारीक
श्रीमती मधु कौशिक

अभिभाषक अपीलांट संख्या 1 ता 5
अभिभाषक अपीलांट संख्या 1
अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर



निर्णय

दिनांक 07.06.2022

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 02.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि -

1- वादग्रस्त भूमि रोही करवा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 444/4 की 6.325 हैक्टेयर भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलांत संख्या 1 के पिता स्व. ख्यालीराम के नाम टी.सी. आवंटित थी। ख्यालीराम की मृत्यु दिनांक 16.03.1994 को हो जाने के बाद उक्त विवादित भूमि का उनके जायज वारिसान के नाम टी.सी. आवंटन नहीं किया जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ ने दिनांक 12.06.2009 को अपीलांत को सम्वत् 2035 से आरजी काश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 02.05.2013 को तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 12.06.2009 को निरस्त कर विवादित भूमि को अराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश दिनांक 02.05.2013 से व्यथित होकर अपीलांतस ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

प्रतिरिक्त प्रमाणित अधिकारी
कार्यालय स. ग. आ. सु.
बीकानेर

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांत श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया है कि रोही करवा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 444/4 में 6.325 हैक्ट. भूमि अपीलांत संख्या 1 के पिता ख्यालीराम पुत्र नन्दराम को सन् 1967-68 में टी.सी. आवंटन की गई थी। ख्यालीराम की मृत्यु दिनांक 16.03.1994 को होने के पश्चात् ख्यालीराम के अधिकार जो गैर खातेदारी के अधिकार थे, वे ख्यालीराम के वारिसान को प्राप्त हो गई थी। सम्वत् 2061 तक वादग्रस्त भूमि का नवीनीकरण करवाया जाता रहा है। उक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 परन्तुक 2 के अन्तर्गत अपीलांत संख्या 1 को तहसीलदार सूरतगढ़ ने दिनांक 12.06.2009 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद भी हो गया। तत्पश्चात् अपीलांत संख्या 1 ने अपनी उक्त 6.325 हैक्ट. भूमि में से 3.162 हैक्ट. भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दी। शेष भूमि अपीलांत संख्या 1 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 4 ता 6 व अपीलांत संख्या 2 ता 5 को विक्रय कर दी। राजस्व रिकार्ड में रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम भूमि का इंतकाल संख्या 377 दिनांक

मिलान किया

सहाय्य आयुक्त
बीकानेर



22.06.2009 को तस्दीक होकर इसका जमाबंदी में अंकन हो चुका था। इसप्रकार अपीलान्त संख्या 1 के अलावा शेष अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ता 6 सदभावी क्रेता है एवं वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई थी। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था, जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि पैराफेरी क्षेत्र से बाहर स्थित है। काशतकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार टीनेन्ट में उसके वारिसान को भी टीनेन्ट माना है। इन परिस्थितियों में आदेश जैर अपील निरस्त करने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्त ने इस संबंध में निम्न रूलिंग्स का हवाला दिया है—


1. RRD 2000 Page 547(A) High Court
2. RRD 2003 Page 197
3. RRD 2008 Page 125
4. RRD 2016 Page 163
5. RRD 1989 Page 667 Camp Jaipur

प्रसाधित

अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य
कार्यालय संभागीय अदालत
बीकानेर

3- विद्वान अभिभाषक अपीलान्त संख्या 01 श्री विजय कुमार पारीक ने बहस **मिलान कयके** दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जारी खातेदारी सनद पूर्ण जांच कर प्रदान की गई थी। टीनेन्सी एक्ट लागू हो चुका है, इसलिए अपील मेन्टेनेबल नहीं है। सक्षम न्यायालय में दावा ही पेश हो सकता था। खातेदारी मिलने के पश्चात् ना ही अपील हो सकती है और ना ही खातेदारी खारिज की जा सकती है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने सक्षम न्यायालय में मियाद अपील पेश की थी। धारा -5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी का कारण अस्वीकार्य है। आवंटन के विरुद्ध अपील का प्रावधान है किन्तु खातेदारी के विरुद्ध अपील का नहीं है। अपील अधिनस्थ न्यायालय में मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। अधिनस्थ न्यायालय में एल आर एक्ट की धारा 75 में अपील पेश की, जिसे सुनने का अधिकार नहीं था। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलान्त ने इस संबंध में निम्न रूलिंग्स का हवाला दिया है—

1. RRD 2008 Page 755
2. RRD 1986 Page 137
3. RRD 2018 Page 479
4. RRD 2004 Page 464
5. RRD 2003 Page 237
6. RRD 1987 Page 179


संभागीय अदालत
बीकानेर



4- विद्वान राजकीय अभिभाषक मोहम्मद इम्तियाज अली ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.06.2009 जिसके द्वारा खातेदारी प्रदान की गई, वह नियम विरुद्ध जाकर की गई है। वादग्रस्त भूमि पैराफेरी क्षेत्र की परिधि के अन्दर है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

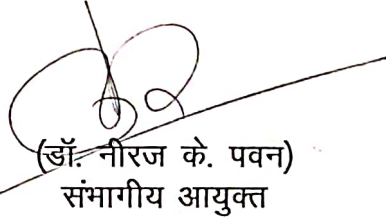
5- हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2013 क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2013 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ अपने निर्णय दिनांक 12.06.2009 के विरुद्ध समक्ष न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं।

मिलान किया
19

6- तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रसासिज

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर


(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर